दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, बुधवार 12 जून 2024 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-06, अंक- 255

महत्वपूर्ण एवं खास

सोने की तस्करी मामले में दो विदेशी महिला मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार

मुंबई (आरएनएस)। मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने अलग-अलग मामलों में दो विदेशी महिला नागरिकों के पास से 19.15 करोड़ रुपये मूल्य का कुल 32.79 किलोग्राम सोना जब्त किया है। जिसकी जानकारी एक अधिकारी की ओर से मंगलवार को साझा की गई। अधिकारी ने बताया कि सोमवार को शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद अफ्रीकी देशों से आई दोनों महिला यात्रियों को संदेह के आधार पर तलाशी ली गई। दोनों मामलों में अंत:वस्त्रों और सामान में छिपाया गया सोना मिला। महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट सीमा विभाग ने 19.15 करोड़ रुपये कीमत का 32.79 किलोग्राम सोना जब्त किया है। दोनों यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सीमा शुल्क अधिकारी फिलहाल इस बात की जांच कर रहे हैं कि उन्हें सोना किसने सप्लाई किया था और इसे मुंबई में किस तक पहुंचाया जाने वाला था।

मुंबई एयरपोर्ट पर ईगेट की संख्या बढ़कर 68 हुई, देश में सर्वाधिक

मुंबई (आरएनएस)। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) पर टर्मिनल एंट्री प्वाइंट्स या ईगेट की संख्या 24 से बढ़कर 68 हो गई है। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि यह देश के किसी भी हवाई अड्डे पर ईगेट की सर्वाधिक उपलब्धता है। बढ़ी हुई क्षमता के साथ सीएसएमआईए के टर्मिनल 2 पर एक घंटे में 7,440 यात्रियों और टर्मिनल 1 पर 2,160 यात्रियों को प्रवेश मिल सकेगा। यह मौजूदा क्षमता से तीन गुना है। इससे सुरक्षा जांच के लिए यात्रियों का प्रतीक्षा समय एक मिनट से भी कम रह जाएगा। इससे डिजी यात्रा और गैर-डिजी यात्रा वाले, दोनों तरह के यात्रियों को आसानी होगी। हवाई अड्डे के एक प्रवक्ता ने डिजी यात्रा के विस्तार के बारे में कहा, ईगेट की संख्या बढ़ाकर और एडवांस बायोमेट्रिक सिस्टम से जोडक़र हम हमारे सभी यात्रियों के लिए सहज, सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीएसएमआईए के डिजिटल गेटवे में प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया की उत्कृष्टता, बिग डाटा एनालिटिक्स और डिजाइन का संयोजन है जो यात्रियों को अनुकरणीय यात्रा अनुभव प्रदान करेगा। बिना किसी बड़े सिविल वर्क के टर्मिनल एंट्री प्वाइंटों की संख्या 24 से बढ़ाकर 68 की गई है। हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर विशेष रूप से डिजी यात्रा के लिए 28 ईगेट और गैर-डिजी यात्रा के लिए 28 गेट हैं। टर्मिनल 1 पर विशेष रूप से डिजी यात्रा के लिए छह ईगेट और गैर-डिजी यात्रा के लिए छह गेट हैं। प्रवक्ता ने बताया कि इसके अलावा प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच के लिए 118 अतिरिक्त ईगेट बनाये जा रहे हैं।

मौज लेने के लिए फ्लाइट में बम होने की झूठी जानकारी देने वाले किशोर पकड़ा गया

नईदिल्ली (आरएनएस)। एयरपोर्ट पुलिस ने मेरठ से एक 13 साल के नाबालिग को पकड़ा है। आरोप है कि बच्चे ने 4 जून की रात साढ़े 11 बजे दिल्ली पुलिस को एक ईमेल के जरिये एक फ्लाइट में बम होने की जानकारी दी थी। ईमेल में बच्चे ने दिल्ली टू टोरंटो जा रही एयर कनाडा की फ्लाइट में बम रखे जाने की जानकारी दी। जिसके चलते आनन फानन में तमाम एजेंसिया हरकत में आ गई और फ्लाइट को 12 घंटे से भी ज्यादा समय तक रोकना पड़ा था। अब इसी मामले की जांच के दौरान एयरपोर्ट पुलिस ने एक 13 साल के बच्चे को पकड़ा है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जिस ईमेल से धमकी दी गई थी उसे महज एक घंटे पहले ही बनाया गया था। ये मेल उत्तर प्रदेश के मेरठ से किया गया था। पुलिस ने मेरठ जाकर जब तफ्तीश शुरू की तो सामने आया कि ये मेल 13 वर्षीय एक बच्चे ने किया था। बच्चे ने बताया कि उसको मुम्बई की एक फ्लाइट में बम की कॉल मीडिया में देखकर ईमेल करने का आईडिया आया। वो ये जानना चाहता था कि पुलिस उसके मेल को ट्रेस कर पाएगी या नहीं, उसने ये धमकी केवल मौज मस्ती के लिए दी थी। पुलिस के मुताबिक बच्चे ने अपने फोन पर एक फर्जी आईडी बनाई और अपनी माँ के फोन के जरिये इंटरनेट को इस्तेमाल किया और ये मेल भेज दिया। मेल भेजने के बाद उसने ये मेल डिलीट भी कर दिया। अगले दिन सुबह उसने टीवी पर देखा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर बम की कॉल चल रही है और वो ये देखकर डर गया। डर की वजह से उसने ये बात अपने घरवालों को नहीं बताई। पुलिस ने बच्चे का फोन जब्त कर लिया है और उसकी काउंसलिंग करवा रही है। बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया।

नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से मांगा जवाब, पर काउंसलिंग पर रोक नहीं

नईदिल्ली। आरएनएस

प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 के रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्र काफी नाराज चल रहे हैं। अब नीट की प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर आज सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

नीट यूजी प्रश्नपत्र लीक होने की खबरों के बीच अभ्यर्थियों के एक समूह ने नए सिरे से एनईईटी-यूजी 2024 परीक्षा कराने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया। गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और फिर से परीक्षा कराई जाए। बता दें, नीट परीक्षा पांच मई को हुई थी और चार जून को रिजल्ट आया था। तभी से कई शिकायतें सामने आई, जिसमें पेपर लीक की बातें कही गईं।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को भी झटका लगा है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पास उम्मीदवारों की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं परीक्षा रद्द करने से भी मना कर दिया।

अवकाश पीठ ने एनटीए से कहा, यह इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आपने यह कराया है, इसलिए इसकी पूरी प्रक्रिया पर अंगुली नहीं उठाई जा सकती। पवित्रता पर असर पड़ा है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता मैथ्यू जे नेदुमपारा ने पीठ से काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का अनुरोध किया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई के लिए आठ जुलाई का समय दिया। पीठ ने कहा, काउंसलिंग शुरू होने दीजिए, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं।

परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर पीठ ने एनटीए को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है, इसलिए एनटीए को जवाब देने की जरूरत है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) की परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।

शीर्ष अदालत ने शिवांगी मिश्रा और अन्य द्वारा दायर याचिका को लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया और एनटीए से इस बीच जवाब दाखिल करने को कहा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नीट-यूजी, 2024 कदाचार से भरा हुआ है, क्योंकि पेपर लीक के विभिन्न मामले याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में आए हैं।

रिजल्ट आने के बाद से ही कई दिनों से छात्र देश के कोनों-कोनों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस याचिका में रिजल्ट वापस लेने और दोबारा परीक्षा की मांग की गई है। वहीं, परीक्षा के रिजल्ट में धांधली की जांच की मांग की गई है। आगे कहा गया कि एनटीए ने मनमानी ग्रेस मार्क दिया है। याचिकाकर्ता ने आशंका जताते हुए कहा कि यह तथ्य सामने आया है कि एक सेंटर विशेष पर एग्जाम दे रहे 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स 720 तक दिए गए हैं। याचिका में आगे कहा गया कि नीट परीक्षा 5 मई को हुई और तभी से कई शिकायतें सामने आई जिसमें पेपर लीक की बातें कही गईं।

ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के रहने वाले अब्दुल्लाह मोहम्मद फैज और शैंक रोशन मोहिद्दीन ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि छात्रों के हितों की खातिर यह याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि इस मामले में जब तक जांच होती है तब तक नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। जानकारी दे दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही दो याचिका लंबित हैं और परीक्षा रद्द कराने की गुहार लगाई जा चुकी है।

साल में दो बार ले सकेंगे उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, द्विवार्षिक प्रवेश चक्र से छात्रों को लाभ

❐ यूजीसी ने दी मंजूरी

नईदिल्ली। आरएनएस

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विदेशी विश्वविद्यालयों की तर्ज पर भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को साल में 2 बार प्रवेश करने की अनुमति दी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, यूजीसी प्रमुख जगदीश कुमार ने बताया कि अगर विश्वविद्यालय साल में 2 बार प्रवेश दे सकें तो छात्रों को फायदा होगा, इससे उन छात्र को लाभ मिलेगा जो बोर्ड के नतीजों में देरी, स्वास्थ्य संबंधी और व्यक्तिगत कारणों से जुलाई-अगस्त सत्र में प्रवेश लेने से चूक गए थे।

जगदीश कुमार ने बताया कि 2024-25 शैक्षणिक सत्र से 2 प्रवेश चक्र जुलाई-अगस्त और जनवरी-फरवरी में होंगे।उन्होंने कहा कि अर्धवार्षिक विश्वविद्यालय प्रवेश से जो छात्र वर्तमान चक्र में प्रवेश से चूक जाते हैं तो उन्हें प्रवेश पाने के लिए एक पूरा साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा।अर्द्धवार्षिक प्रवेश के साथ, उद्योग से जुड़े संस्थान भी साल में 2 बार अपने नौकरी के लिए कैंपस भर्ती कर सकते हैं, जिससे स्नातकों के लिए रोजगार के अवसर बेहतर होंगे।

जगदीश कुमार ने कहा कि यह आदेश अनिवार्य नहीं है। जिन विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं के पास शिक्षक संकाय और जरूरी संसाधन हैं, वे इसका लाभ उठा सकते हैं।उन्होंने कहा कि दुनिया भर के विश्वविद्यालय साल में 2 बार प्रवेश प्रणाली का पालन करते हैं। अगर भारत में विश्वविद्यालय द्विवार्षिक प्रवेश का उपयोग करते हैं तो उनको संकाय, प्रयोगशाला, कक्षाएं और सहायक सेवाओं की योजना अधिक कुशलतापूर्वक बनाने में मदद मिलेगी।

रियासी में आतंकी हमला करने वालों की अब खैर नहीं, सीआरपीएफ की 11 टीमों ने कर दी घेरा बंदी

श्रीनगर। आरएनएस

जम्मू और कश्मीर में तीर्थयात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बाद इस मामले में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं. घाटी से मिल रही ताजा जानकारी के मुताबिक अब इस आतंकी हमला करने वालों की खैर नहीं है. इसके लिए सेना की ओर से घेराबंदी शुरू हो गई है. सेना और सीआरपीएफ की कुल 11 टीमों को इन आतंकियों की तलाश में तैनात कर दिया है. बता दें कि पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए अब सेना एक्शन मोड में है. इसके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है. दरअसल बस पर हमला करने के बाद सभी आतंकी जंगल की ओर से भाग गए थे. यही वजह है कि सेना के जवानों ने अब रियासी जंगल को पूरी तरह घेर लिया है.

रियासी के जंगलों में आतंकियों को खोजने के लिए कमांडो के साथ-साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. ड्रोन के जरिए जंगल के चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है और जहां पर आतंकियों की गतिविधि की जानकारी लगेगी वहां तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

9 जून रविवार को जब नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेना थी, उसी दिन जम्मू-कश्मीर में सुबह तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि ये आतंकी पहले से ही घात लगाकर बैठे थे. इस हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी. वहीं 41 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे. हमला जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में हुआ. तीर्थयात्रियों से भरी बस शिवखोड़ी मंदिर से माता वैष्णोदेवी मंदिर की ओर लौट रही थी.

आतंकियों ने सबसे पहले बस के ड्राइवर पर निशाना साधा और उसे गोली मारी. इस अटैक के बाद ड्राइव का बस से नियंत्रण छूट गया और बस नीचे खाई में जा गिरी. इसके बाद भी आतंकी बस पर फायरिंग करते रहे इसमें ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही मौके पर ही मौत हो गई.

इस मामले की जांच में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनआईए जुटी है. इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेसिसटेंस फ्रंट ने ली है. टीआरएफ को 2023 में भारत ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया था. बहरहाल घटना स्थल पर अब भारतीय सेना और सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन जारी है. किसी भी वक्त इन गुनहगारों को शिकंजे में लिया जा सकता है.

24 साल बाद ओडिशा को मिला नया सीएम, मोहन मांझी बनेंगे मुख्यमंत्री

❐ भाजपा विधायक दल की बैठक में फैसला

भुवनेश्वर। आरएनएस

ओडिशा विधानसभा चुनाव 2024 में पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली भाजपा ने राज्य के नए मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया है।भाजपा नेता मोहन मांझी राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही ओडिशा को 24 साल बाद नया मुख्यमंत्री मिल गया है।इसके अलावा प्रवती परिदा और कनक वर्धन सिंह देव उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्य की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को भुवनेश्वर में होगा।

नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव दोपहर में पर्यवेक्षक के रूप में राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे थे।इसके बाद वहां भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई। उसमें मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई।इसके बाद शाम करीब 6 बजे राजनाथ सिंह ने राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में मोहन मांझी और उपमुख्यमंत्री के रूप में प्रभाती और केवी सिंह के नाम की घोषणा कर दी।

मांझी ओडिशा में आदिवासी समाज का प्रमुख चेहरा हैं और भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर इस समाज पर अपनी पकड़ मजबूत करने की ओर भी कदम उठाया है।मांझी ओडिशा की क्योंझर सीट से विधानसभा चुनाव जीते हैं और यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।उन्होंने इस सीट से बीजू जनता दल (बीजद) के नीना मांझी को 11,577 वोट से मात दी थी। 52 वर्षीय मांझी चार बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं।

मांझी ने अपने रानजीतिक करियर की शुरुआत सरपंच पद से की थी। वह साल 1997 से 2000 तक सरपंच रहे थे। इसके बाद साल 2000 में उन्होंने क्योंझर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और उसमें जीत हासिल कर विधानसभा का रास्ता तय किया था।

राज्य के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली प्रवती ने निमापारा से विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है।उन्होंने बीजद के दिलिप कुमार नायक को 4,588 वोट से मात दी थी।ओडिशा के दूसरे उपमुख्यमंत्री बनने जा रहे कनक वर्धन पटनगढ़ से विधायक हैं और उन्होंने एक करीबी मुकाबले में बीजद के सरोज कुमार मेहर को 1,357 वोट से मात दी है।यह पहली बार होगा जब ओडिशा में दो उपमुख्यमंत्री भी होंगे।

भाजपा ने विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 147 सीटों में से 78 पर कब्जा जमाते हुए पूर्ण बहुमत हासिल किया है।इसी तरह बीजद 51 सीटों के साथ बहुमत से दूर रह गई। इसके साथ राज्य में पिछले 24 सालों से बरकरार बीजद की सत्ता का अंत हो गया है।राज्य में 2000 से 2024 तक नवीन पटनायक मुख्यमंत्री रहे थे। वह 24 साल 98 दिन इस पद पर रहे। अब राज्य को नया मुख्यमंत्री मिल गया है।

ओडिशा में भाजपा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भुवनेश्वर के जनता मैदान पर होगा।इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।इसके अलावा साधु-संतों को भी आमंत्रण भेजा गया है। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की जनता से वादा किया था कि उनकी सरकार में कोई उडिय़ा भाषा बालने वाला व्यक्ति ही मुख्यमंत्री होगा।

देश में अवैध रूप से घुसे चीनी नागरिक की अस्पताल में मौत

❐ आत्महत्या की नीयत से खुद को किया था जख्मी

मुजफ्फरपुर। आरएनएस

बिहार के मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में इलाजरत चीन के एक नागरिक की मंगलवार को मौत हो गई। उसे भारत में अवैध रूप से घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मुजफ्फरपुर के ब्रहपुरा थाना क्षेत्र में छह जून को बिना वीजा के देश में घुसने के आरोप में पकड़ा गया चीनी नागरिक ली जियाकी की मंगलवार की सुबह मौत हो गई।

आत्महत्या के प्रयास के बाद घायल अवस्था में चीनी नागरिक को श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ली जियाकी को अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा भेज दिया गया था। जेल में जियाकी ने सात जून को आत्महत्या का प्रयास किया था। बंदियों से पूछताछ में पता चला था कि चीनी नागरिक ने अपने चश्मे के शीशे को तोडक़र खुद को जख्मी करने का प्रयास किया था, जिससे वह शौचालय में ही बेहोश हो गया। जेल प्रशासन ने जियाकी को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उस समय जेल प्रशासन ने कहा था कि जियाकी ने आत्महत्या की कोशिश की है। इलाज के दौरान शरीर के कई अंगों में घाव के गहरे निशान मिले थे। उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। मंगलवार सुबह जियाकी की मौत हो गई।

फिर शुरू होगा हीट वेव का असर, कई दिनों तक नहीं मिलेगी भीषण गर्मी से राहत

नई दिल्ली। आरएनएस

दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर हीट वेव का असर देखने को मिलने वाला है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 12 जून से लेकर 17 जून के बीच हीट वेव का असर देखने को मिल सकता है और पारा 45 डिग्री के पार पहुंच जाएगा।

11 जून तक पारा 44 डिग्री के पार दिख रहा है। डॉक्टरों की सलाह है कि हीट वेव के दौरान घरों से बिल्कुल ना निकलें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं ताकि डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो पाएं। मौसम विभाग के आंकड़ों की मानें तो 11 जून को आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है और पारा 44 डिग्री के पार पहुंच सकता है। वहीं 12 जून से लेकर 13, 14, 15, 16 और 17 जून तक पारे के 45 डिग्री से ज्यादा पहुंचने की संभावना जताई गई है।

साथ ही साथ किसी भी तरीके के कोई भी बादल छाने या बारिश या तेज तूफान के असर को भी मौसम विभाग ने नहीं दिखाया है। इससे साफ तौर पर जाहिर है कि एनसीआर वालों को एक बार फिर भीषण और तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है और हीट वेव के चलने के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा।

गौरतलब है कि बीते दिनों दिल्ली में पारा 50 डिग्री के भी पार पहुंच गया था और बिजली की आपूर्ति भी अपने बीते रिकॉर्ड को तोड़ चुकी थी। नोएडा-ग्रेटर नोएडा में भी बिजली आपूर्ति में होने वाली बाधा के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग लगातार सडक़ों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

योगी सरकार का एक्शन, ट्रांसफर पॉलिसी से लेकर सैलरी पर लिए बड़े फैसले

लखनऊ। आरएनएस

उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दरअसल योगी सरकार ने कर्मचारियों से जुड़े बड़े फैसले लिए हैं. मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी. इस बैठक में ट्रांसफर से लेकर सैलरी बढ़ोतरी से जुड़ी कई मामलों पर बड़े फैसले लिए गए. बैठक में यूपी के सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर से जुड़ा अहम निर्णय भी लिया गया है. इसके तहतत अब ग्रुप सी और डी स्तर के सरकारी कर्मचारियों के तबादले मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे.

योगी सरकार ने 11 जून को कैबिनेट मीटिंग में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया. इसके तहत सी और डी स्तर के सरकारी कर्मियों के तबादले अब मानव संपदा पोर्टल के जरिए होंगे. यही नहीं अब आसानी से किसी भी सरकारी कर्मचारी के ट्रांसफर किए जा सकेंगे. इस बैठक में योगी सरकार ने 41 प्रस्तावों को तुरंत मंजूरी दे दी है. दरअसल मीटिंग के दौरान 42 प्रस्ताव पेश किए गए थे, इनमें से एक प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी जबकि बाकी 41 प्रस्तावों को पास कर दिया गया.

तबादला नीति में क्या बदलाव

- योगी सरकार ने तबादला नीति में अहम बदलाव के बाद इसे आसान बना दिया है.
- मानव संपदा पोर्टल के जरिए ट्रांसफर होंगे.
- विभागाध्यक्षों को महज 19 दिन में ट्रांसफर मिल जाएगा.
- 30 जून तक सभी विभागाध्यक्ष कर सकेंगे ट्रांसफर
- नई नीति में ग्रुप क और ख के कर्मचारियों की कुल संख्या का 20 फीसदी हो सकेगा ट्रांसफर
- वहीं ग और घ के कर्मचारियों का अधिकतम 10 फीसदी ट्रांसफर ले सकेंगे.

सैलरी में भी होगा इजाफा

कैबिनेट मीटिंग पर योगी सरकार ने वेतन वृद्धि से जुड़ा अहम फैसला लिया है. दरअसल सरकार के फैसले के तहत वेतन वृद्धि से एक दिन पहले रिटायर होने वाले राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने का फैसला लिया गया है.

इन फैसलों पर लगी मुहर

- ग्रेटर नोएडा में 500 बेड के अस्पताल को मिली मंजूरी
- आईआईटी कानपुर में बनेगा मेडिकल रिसर्च सेंटर
- लखीमपुर में एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी, इसके तहत आने वाले गांवों की 655 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी.
- बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी तो गाजियाबाद में एचआरआईटी यूनिवर्सिटी को भी बैठक में मिली मंजूरी.
- हुडको से 100 करोड़ के लिए लोन की गारंटी सरकार लेगी